प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
22.09.2024 / प्रादेशिक समाचार / 19:45 बजे

मुख्य समाचार''

- केन्द्र सरकार ने युवाओं में तम्बाकू के सेवन की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को जारी किया परामर्श।
- राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आयुर्वेद के पुरातन ज्ञान के संरक्षण की आवश्यकता पर दिया बल।
- मुख्यमंत्री ने कहा– वंचित वर्गो के बच्चों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित बनाने के लिए सरकार ने उठाए कई कदम।
- विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर चुनावी वायदों के विपरीत काम करने का लगाया आरोप।

परामर्श

केंद्र सरकार ने युवाओं में तंबाकू के सेवन की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया है। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने मुख्य सचिवों को तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में दिशा–निर्देश और मैनुअल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कहा है। इसका लक्ष्य तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ–साथ तंबाकू नियंत्रण उपायों को बढ़ावा देकर भावी पीढ़ियों की रक्षा करना है। परामर्श में ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे–2019 के निष्कर्षों के हवाले से विशेष रूप से बच्चों और किशोरों पर तंबाकू सेवन के खतरनाक प्रभावों का उल्लेख किया गया है। इस सर्वे में पता चला है कि भारत में 13 से 15 वर्ष की आयु के साढ़े 8 प्रतिशत स्कूली छात्र तंबाकू का सेवन करते हैं।

राज्यपाल

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आयुर्वेद के पुरातन ज्ञान के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है। वे कल देर शाम नई दिल्ली में भारतीय धरोहर के 8वें वार्षिक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रकृति परीक्षण की अवधारणा पर शोध होना चाहिए जोकि शरीर के विभिन्न रोगों का निदान करने पर केन्द्रित है। राज्यपाल ने प्राचीन ज्ञान के संरक्षण और समाज सेवा के लिए भारतीय धरोहर की समर्पित सेवाओं की सराहना की। उन्होंने भारतीय धरोहर की वार्षिक पत्रिका का विमोचन भी किया। भारतीय धरोहर के महामंत्री विजय शंकर तिवारी ने संगठन की विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

भेंट

इस बीच प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने आज शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा चलाए गए एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम सहित विभिन्न सामाजिक विषयों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम एक वृक्षारोपण अभियान है जिसकी शुरूआत प्रधानमंत्री ने इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर की थी। इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का पर्यावरण संरक्षण में योगदान सुनिश्चित बनाना है।

मुख्य न्यायाधीश

दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राजीव शकधर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। वे मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव की जगह लेंगे। न्यायाधीश राजीव शकधर को 11 अप्रैल 2008 को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

पोर्टल

ऑनलाइन ख़रीदारी के लिए सरकारी पोर्टल जी.ई.एम. ने खरीदारी को आसान बनाने और अर्थव्यवस्था को अधिक समावेशी बनाने के लिए विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए शुल्क को कम कर दिया है। नई व्यवस्था के अनुसार, अब दस लाख रुपये तक की खरीद पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। पहले यह सीमा पांच लाख रुपये ही थी। दस लाख से दस करोड़ रुपये तक की खरीद पर अब केवल शून्य दशमलव तीन शून्य प्रतिशत शुल्क देय होगा। दस करोड़ रुपये से अधिक की खरीद पर तीन लाख रुपये का एक समान शुल्क लगेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय सरकार की 100 दिनों की पहल का हिस्सा था।

बाली

पर्यटन निगम के अध्यक्ष आर.एस.बाली ने कहा है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य संस्थानों के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दे रही है। इसके तहत नियमित तौर पर चिकित्सकों और पैरामैडिकल स्टाफ के पदों को भरने के लिए तत्परता से कार्य किया जा रहा है ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। वे कांगड़ा के टांडा मैडिकल कॉलेज में विश्व फॉर्मेसी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। बाली ने कहा कि टांडा मैडिकल कॉलेज भी स्वास्थ्य क्षेत्र में निरंतर नए आयाम स्थापित कर रहा है।

डीसी चंबा

चंबा के उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने जिले में सभी विभागों के अधिकारियों को ''नारी शक्ति से जल शक्ति'' थीम के अनुरूप जल संरक्षण से जुड़े जागरूकता कार्यों में महिलाओं का सहयोग लेने को कहा है। चंबा में एक बैठक के दौरान उन्होंने उद्यान विभाग के अधिकारियों को इस वित्त वर्ष के दौरान बनाए जाने

वाले जल भंडारण टेंकों की सूची को जल शक्ति विभाग के साथ साझा करने के निर्देश भी दिए। उपायुक्त ने जिला विकास अधिकारी को वन सरोवर के निर्माण को लेकर भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश के वंचित वर्गों के बच्चों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए है। इस उद्देश्य से सरकार ने डॉक्टर वाई. एस. परमार ऋण योजना को विस्तार प्रदान किया है। इसके तहत विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा इसके लिए जल्द ही मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी जाएगी। योजना के अंतर्गत पात्र बोनोफाईड हिमाचली विद्यार्थियों को केवल एक प्रतिशत ब्याज दर पर शैक्षिक ऋण देने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 2 सौ करोड़ रूपए का बजट आबंटित किया है।

जयराम ठाकुर

विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर चुनावी वायदों के विपरीत काम करने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस ने जनता से कई लोक लुभावन वायदे किए थे लेकिन सत्ता में आने के बाद से सभी सुविधाएं छीनी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बिजली पर मिलने वाली एक सौ 25 युनिट की सब्सिडी बंद करने के बाद अब लोगों को मिल रहे निशुल्क पानी की योजना को भी खत्म कर दिया है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में पानी की दरों में भारी वृद्धि की गई है, जिसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ना तय है। जयराम ठाकुर ने ये भी आरोप लगाया कि इसके साथ ही सरकार द्वारा विकास कार्यों को अटकाने और लटकाने का भी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कई योजनाएं बंद की है और कई योजनाओं का बजट भी रोक दिया है।

भाजपा

इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी राज्य सरकार द्वारा पानी की दरों में की गई वृद्धि के निर्णय को जनविरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में भी पानी की दरों में कई गुना वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार हर चीज मुफ्त में देने का वायदा कर सत्ता में आई थी लेकिन सत्ता में आने के बाद से सरकार ने जनता के लिए मंहगाई बढ़ाने का कार्य किया है।

शांडिल

स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रखने के लिए सभी के एकजुट प्रयास जरूरी है। सोलन जिले के कंडाघाट में एक खेल प्रतियोगिता के समापन पर उन्होंने कहा कि खेलकूद गतिविधियां युवाओं को नशे से दूर रखने में अहम भूमिका निभा सकती है। शांडिल ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए कारगर कदम उठा रही है और सभी विद्यालयों में खेल गतिविधियों के लिए आधारभूत संरचना विकसित की जा रही है। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न खेलों के विजेता खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। प्रतियोगिता में सोलन जिले के 46 स्कूलों के छात्र–छात्राओं ने हिस्सा लिया।

आउटरीच

हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय शिमला के कानूनी सहायता क्लिनिक ने शिमला ग्रामीण के विभिन्न वार्डों में आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान प्रतिनिधियों ने क्लिनिक द्वारा दी जाने वाले मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं की जानकारी दी गई। इसके अलावा लोगों को कानूनी अधिकारों से भी अवगत करवाया गया।

मुख्य समाचार एक बार फिर''

- केन्द्र सरकार ने युवाओं में तम्बाकू के सेवन की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को जारी किया परामर्श।
- राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आयुर्वेद के पुरातन ज्ञान के संरक्षण की आवश्यकता पर दिया बल।
- मुख्यमंत्री ने कहा– वंचित वर्गो के बच्चों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित बनाने के लिए सरकार ने उठाए कई कदम।
- विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर चुनावी वायदों के विपरीत काम करने का लगाया आरोप।

.....